लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1185

14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रीन और ब्राउन फील्ड परियोजनाएं

1185. श्री राजा अमरेश्वर नाईकः
श्री भोला सिंह:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकांत मजूमदार:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में मेगा कितने मेगा हथकरघा क्लस्टर कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी ग्रीन और ब्राउनफील्ड परियोजनाओं का चयन किया गया है;

(ङ) इस योजना की अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सीएचसीडीएस के अंतर्गत कर्नाटक में मेगा हथकरघा समूहों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदनार्थ लंबित है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (छ): मेगा हथकरघा क्लस्टर के एकीकृत और समग्र विकास के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान शामिल किया गया है, जिसमें 5 साल की अवधि में कम से कम 10,000 हथकरघों के लिए 30 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

विभिन्न वार्षिक बजटों में घोषणा के अनुसार, 9 मेगा हैंडलूम क्लस्टर अर्थात वाराणसी (उत्तर प्रदेश), सिवसागर (असम), विरुधुनगर (तमिलनाडु), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), प्रकाशम और गुंटूर जिले (आंध्र प्रदेश), गोड्डा और पड़ोसी जिले (झारखंड), भागलपुर (बिहार) और त्रिची (तमिलनाडु) और इम्फाल पूर्व (मणिपुर) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, कोई भी ग्रीन फील्ड अथवा ब्राउन फील्ड परियोजना शुरू नहीं की गई है।

मेगा हथकरघा क्लस्टरों में, आवश्यकता आधारित अंतःक्षेपों जैसे हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास/विविधीकरण, बाजार विकास, निर्यात और प्रचार, तकनीकी/सामान्य अवसंरचना का विकास, मूल्य वर्धन इकाइयों जैसे गारमेंटिंग (परिधान), प्रोसेसिंग मुद्रण इकाइयों आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 80% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है जबकि भूमि सहित परियोजना लागत का 20% राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है।

वस्त्र मंत्रालय में कर्नाटक राज्य से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

******